



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1600]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2010/श्रावण 13, 1932

No. 1600]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2010/SHRAVANA 13, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2010	(1)	(2)	(3)	(4)
का.आ. 1909(अ).—यतः, मै. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन, जो महाराष्ट्र राज्य में एक निजी संगठन है, ने महाराष्ट्र राज्य में ग्राम सुरवादी एवं नन्दल, तालुका फाल्तान, जिला सतारा में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;	3.	नन्दल	244/1	4.24
	4.		244/2	0.81
	5.		245	0.66
	6.		246	0.68
	7.		247	0.70
	8.		248	0.71
	9.		249 भाग	3.75
	10.		250	2.00
	11.		251	2.09
	12.		252	4.03
	13.		253	1.86
	14.		254/1	0.80
	15.		254/2	1.94
	16.		255	1.41
	17.		256	1.74
	18.		257	1.60
	19.		258	0.58
	20.		259	0.64
	21.		260	1.31
	22.		261	1.22
	23.		262	1.29
	24.		326	0.50
	25.		380	4.39
	26.		381	0.52
	27.		382	1.85
	28.		383	4.46
	29.		384	6.44
	30.		385	1.80
	31.		386	1.75
	32.		387	3.32
	33.		388	1.53
	34.		389	1.55
	35.		390	0.79
अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—				
तालिका				
क्र.सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	नन्दल	242	2.61	
2.		243	0.05	

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	सुरवादी	62 भाग	8.00
37.		63	1.42
38.		64	1.39
39.		65/1	0.40
40.		66	0.97
41.		67	2.25
42.		74/बी/2	1.14
43.		76/2	0.59
44.		78/2	0.81
45.		79	2.45
46.		80	3.04
47.		81	7.48
48.		82 भाग	4.00
49.		83/1 भाग	0.125
50.		82/2 भाग	0.125
51.		86 भाग	1.44
		कुल	101.25
			हेक्टेयर

और यतः विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, —सदस्य, पदेन
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या
उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव,
भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन
क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त
विदेश व्यापार महानिदेशक
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन
क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क
आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त
आयुक्त से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन
क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त
अथवा उसका नामिती जिसका स्तर
संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
- निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, —सदस्य, पदेन
बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किए —सदस्य, पदेन
जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर
संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा

- मै. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट —विशेष
कॉरपोरेशन (जोन के विकासकर्ता) आमंत्रिता
का प्रतिनिधि

और यतः विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 4 अगस्त, 2010 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/224/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2010

S.O. 1909(E).—Whereas, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation, a State Government agency in the State of Maharashtra, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for engineering at Villages Survadi and Nandal, Taluka Phaltan, District Satara in the State of Maharashtra;

And, whereas, the Central Government is satisfied, that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on the 4th December, 2008;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Village	Survey Number	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nandal	242	2.61
2.		243	0.05
3.		244/1	4.24
4.		244/2	0.81
5.		245	0.66
6.		246	0.68
7.		247	0.70

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Nandal	248	0.71
9.		249 Part	3.75
10.		250	2.00
11.		251	2.09
12.		252	4.03
13.		253	1.86
14.		254/1	0.80
15.		254/2	1.94
16.		255	1.41
17.		256	1.74
18.		257	1.60
19.		258	0.58
20.		259	0.64
21.		260	1.31
22.		261	1.22
23.		262	1.29
24.		326	0.50
25.		380	4.39
26.		381	0.52
27.		382	1.85
28.		383	4.46
29.		384	6.44
30.		385	1.80
31.		386	1.75
32.		387	3.32
33.		388	1.53
34.		389	1.55
35.		390	0.79
36.	Surwadi	62 Part	8.00
37.		63	1.42
38.		64	1.39
39.		65/1	0.40
40.		66	0.97
41.		67	2.25
42.		74/B/2	1.14
43.		76/2	0.59
44.		78/2	0.81
45.		79	2.45
46.		80	3.04
47.		81	7.48
48.		82 Part	4.00
49.		83/1 Part	0.125
50.		82/2 Part	0.125
51.		86 Part	1.44
		Total	101.25
			hectares

And, Therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) hereby

constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone —Chairperson ex-officio;
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Mamber, ex-officio;
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone —Member, ex-officio;
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio;
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio;
6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India —Member, ex-officio;
7. Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Maharashtra —Member, ex-officio;
8. Representative of M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation (Developer of the Zone) —Special Invitee.

And, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) hereby appoints the 4th day of August, 2010 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/224/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.